आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 17 अंक : 28 लखनऊ, बुद्धवार 28 अक्तूबर 2026 स 06 नवम्बर 2026 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

बिरला ने चीन को सौंपी १३वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को १२वें ब्रिक्स संसदीय मंच के समापन समारोह में संयुक्त घोषणा पत्र अंगीकार किए जाने के बाद चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के उपाध्यक्ष झेंग जियानबांग को १३वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता औपचारिक रूप से सौंप दी। श्री बिरला ने संसद भवन परिसर स्थित संविधान सदन में दो दिन चले १२वें ब्रिक्स संसदीय मंच के आयोजन के समापन समारोह में चीन को अगले वर्ष होने वाले १३वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता सौंपी। श्री झेंग ने १२वें ब्रिक्स संसदीय मंच की सफलता के लिए श्री बिरला को धन्यवाद दिया और कहा कि चीन १३वें मंच के सफल आयोजन तथा संसदीय विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। उन्होंने १२वें संसदीय मंच की सफलता को एकजुटता के साथ किए गए सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया और कहा कि चीन में कहावत है कि जब लोग मिलकर



और एकजुट होकर प्रयास करते हैं, तो परिणाम बहुत अच्छे होते हैं और भारत ने इसे करके दिखाया है। श्री झेंग ने ब्रिक्स के विकास के प्रति चीन की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने १२वें ब्रिक्स संसदीय मंच के माध्यम से विकास की जिस यात्रा को आगे बढ़ाया है, चीन उसे और आगे ले जाने के लिए प्रयास करेगा। इससे पहले, सम्मेलन से इतर श्री बिरला और श्री झेंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें दोनों नेताओं ने संसदीय आदान–प्रदान, नियमित संवाद तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से भारत–चीन संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री बिरला ने कहा कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत और चीन की साझा जिम्मेदारी है कि वे सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखें तथा संवाद और आपसी सम्मान के माध्यम से मतभेदों का सौहार्दपूर्ण समाधान करें। उन्होंने कहा कि दिल्ली घोषणा पत्र दक्षिण गोलार्द्ध के विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण है। पिछले २० साल में ब्रिक्स का विकास हुआ है और चीन इसके विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है।

ब्रिक्स संसदीय मंच के घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई

नई दिल्ली। ब्रिक्स संसदीय मंच ने विश्व में आतंकवाद की कड़ी निंदा की है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ



कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नयी दिल्ली में आयोजित दो दिन के १२वें ब्रिक्स संसदीय मंच की बैठक में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव की जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह मंच दुनिया में शांति, विकास और सहयोग की मजबूत आवाज बन सकता है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में संयुक्त घोषणा पत्र में आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई है तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आतंकवादी घोषित व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ ठोस कार्रवाई किये जाने की आवश्वयकता पर बल दिया गया है। श्री बिरला ने कहा कि घोषणा पत्र में डिजिटल औद्योगिकी को समावेशी बनाने और देशों के आंतरिक मामले में बाहरी दखल के निषेध की भी पुरजोर मांग की गई है। श्री बिरला ने समापन समारोह में ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता चीन को सौंपी।

चौक स्टेडियम में दो दिवसीय परिषदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ, पहले दिन बीकेटी के खिलाड़ियों का दबदबा

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से मंगलवार, २७ अक्टूबर २०२६ को चौक स्टेडियम



में दो दिवसीय जनपद स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ विपिन कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। उद्घाटन समारोह में ध वजारोहण के बाद प्रतिभागी खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन की शपथ दिलाई गई। इसके बाद पिछले वर्ष की विजेता धावक ने मशाल दौड़ लगाकर प्रतियोगिता की विधिवत शुरुआत की। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बेहटा, बीकेटी की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। प्राथमिक विद्यालय बखारी की बालिकाओं ने स्वागत गीत से अतिथियों का अभिनंदन किया, जबकि सरोजनी नगर के बेसिक विद्यालय बीबीपुर की छात्राओं ने राजस्थानी लोकनृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन प्राथमिक स्तर की विभिन्न खेल स्पर्धाएं आयोजित की गईं। बालक वर्ग की ५० मीटर दौड़ में बीकेटी के अखिल, १०० मीटर दौड़ में मोहनलालगंज के शिवम और २०० मीटर दौड़ में बीकेटी के आदर्श ने प्रथम स्थान हासिल किया। लंबी कूद में भी बीकेटी के रितिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की। बालिका वर्ग में बीकेटी की तान्या ने ५० मीटर और २०० मीटर दौड़ में विजेता बनकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। १०० मीटर दौड़ में बीकेटी की आराधना रावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं, ४०० मीटर दौड़ में मोहनलालगंज की क्रांति और लंबी कूद में बीकेटी की पल्लवी विजेता बनीं। टीम स्पर्धाओं में बालक वर्ग की खो–खो प्रतियोगिता में काकोरी की टीम विजेता रही, जबकि कबड्डी में मोहनलालगंज की टीम ने जीत हासिल की। बालिका वर्ग की खो–खो प्रतियोगिता में गोसाईंगंज और कबड्डी में माल ब्ल क की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अन्य प्रतियोगिताओं में व्यायाम प्रदर्शन और समूहगान में



बीकेटी की टीम ने बाजी मारी, जबकि अंत्याक्षरी में गोसाईंगंज की टीम विजेता बनी। योग प्रतियोगिता के बालक वर्ग में गोसाईंगंज और बालिका वर्ग में बीकेटी की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय रामराज, आरपी यादव, सुशील कुमार, प्रीति शुक्ला, पूनम मिश्रा, व्यायाम शिक्षक नीलम सिंह और संजय पांडे सहित बड़ी संख्या में शिक्षक–शिक्षिकाएं तथा खेल अनुदेशक उपस्थित रहे। दो दिवसीय प्रतियोगिता के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। प्रतियोगिता में विभिन्न ब्ल कों के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

सम्पादकीय

जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल

भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। इसके तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग–अलग दायित्व सौंपे गए हैं, ताकि कोई भी संस्था निरंकुश न हो सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता इसी व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने विभिन्न निर्णयों में इसे संविधान के मूलभूत ढांचे का अंग माना है। इसी अवधारणा के आधार पर १९९३ और १९९८ के ऐतिहासिक फैसलों के बाद उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली विकसित हुई। हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में निर्वाचित सरकार और संसद की भूमिका सीमित हो गई है, जबकि समर्थकों का मानना है कि इससे न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से बचाने में मदद मिलती है। भारत में कॉलेजियम प्रणाली को लेकर बहस केवल नियुक्तियों की प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्यायपालिका की स्वायत्तता, पारदर्शिता और जवाबदेही से भी जुड़ी है। दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अलग–अलग व्यवस्थाएं हैं, जिनमें सरकार, संसद और स्वतंत्र चयन संस्थाओं की भूमिका होती है। भारत की व्यवस्था विशिष्ट है, लेकिन इसका औचित्य तभी बना रह सकता है, जब नियुक्ति प्रक्रिया निष्पक्ष हो और उसमें किसी बाहरी दबाव की गुंजाइश न रहे। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पूर्व प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में की गई टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं। न्यायमूर्ति कौल के अनुसार, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव भेजने से पहले संबंधित नामों पर सरकार की मंजूरी लेते थे। उन्होंने इसे सरकार के प्रति अत्यधिक सम्मान की भावना से जोड़कर देखा। यदि इन टिप्पणियों का आशय यही है कि नियुक्तियों के मामले में सरकार की सहमति को प्राथमिकता दी जाती थी, तो इससे क लेजियम की वास्तविक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठते हैं। हालांकि, किसी पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी को अपने आप में अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। यह समझना भी जरूरी है कि सरकार से विचार–विमर्श करना और सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया में निर्णायक अधिकार देना दो अलग–अलग बातें हैं। यदि किसी नाम पर सरकार की राय जानना केवल प्रशासनिक संवाद का हिस्सा था, तो उसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्पण नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि सरकार की सहमति के बिना कॉलेजियम अपने निर्णय पर आगे बढ़ने में असमर्थ था, तो यह व्यवस्था की मूल भावना के विपरीत स्थिति होगी। इसलिए इन आरोपों और दावों का निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक है। दरअसल, कॉलेजियम प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अपारदर्शिता मानी जाती है। न्यायाधीशों के चयन के मानदंड, नामों पर विचार की प्रक्रिया और किसी नाम को स्वीकार या अस्वीकार करने के आधारों के बारे में पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक नहीं होती। इससे भाई–भतीजावाद, पक्षपात और बंद कमरे में फैसले किए जाने की आशंकाएं जन्म लेती हैं। दूसरी ओर, यदि नियुक्तियों में कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ता है, तो राजनीतिक विचारधारा के आधार पर चयन या असहमति रखने वाले न्यायाधीशों की उपेक्षा का खतरा भी पैदा हो सकता है। इसीलिए समाधान किसी एक संस्था को असीमित अधिकार देने में नहीं, बल्कि संतुलित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रक्रिया विकसित करने में है। न्यायपालिका केवल कानून की व्याख्या करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संविधान की संरक्षक भी है। उसकी विश्वसनीयता पर उठने वाले सवालों का असर पूरी संवैधानिक व्यवस्था पर पड़ता है। ऐसे में वर्तमान न्यायाधीशों और क लेजियम को इन चर्चाओं को गंभीरता से लेना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया के मानदंड स्पष्ट किए जाने चाहिए और निर्णयों के आधारों को यथासंभव सार्वजनिक किया जाना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ सरकार से टकराव नहीं, बल्कि किसी भी अनुचित दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेना है। इसी तरह, स्वायत्तता का अर्थ जवाबदेही से छूट भी नहीं हो सकता। कॉलेजियम की साख तभी कायम रह सकती है, जब वह अपनी स्वतंत्रता के साथ पारदर्शिता और निष्पक्षता का भरोसा भी दे। संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न तो सरकार की कृपा पर निर्भर हो और न ही किसी बंद व्यवस्था की मनमर्जी पर।

यूपी में १,९२६ करोड़ रुपये का निवेश, ग्रेटर नोएडा में हायर की परियोजना और प्रयागराज में बनेगा ताज का लग्जरी होटल

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश में १,९२५.९१ करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एफडीआई, विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई) तथा फ र्च्यून ग्लोबल ५०० एवं फ र्च्यून इंडिया ५०० निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत दो कंपनियों के प्रस्ताव स्वींत किए गए। इसके साथ ही संबंधित कंपनियों को लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने की मंजूरी भी दी गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक गतिविधियों और प्रयागराज में पर्यटन एवं आतिथ्य सेवाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। फॉर्च्यून इंडिया ५०० में शामिल हायर अप्लायंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा में १,२७१ करोड़ रुपये की लागत से अपनी परियोजना स्थापित करेगी। यह परियोजना दिल्ली–मुंबई औद्योगिक क रिडोर के अंतर्गत विकसित की जा रही स्मार्ट एवं इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थापित होगी। इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलने और आधुनिक औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास को गति मिलने की संभावना है। मंत्रिपरिषद ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एकावो ह स्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ६५४.६१ करोड़ रुपये की ग्रीनफील्ड लग्जरी होटल परियोजना को भी मंजूरी दी है। प्रस्तावित होटल में लगभग १५८ कमरे और सुइट्स बनाए जाएंगे। इसका संचालन इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा ताज समूह के गेटवे ब्रांड के अंतर्गत किया जाएगा। होटल में बैंक्वेट, रेस्टोरेंट और एकीकृत वाणिज्यिक परिसर के साथ कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इनमें डाइनिंग हॉल, एक्जीबिशन ह ल,



स्पा, जिम, स्विमिंग पूल, रिटेल और मल्टीप्लेक्स जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे होटल में ठहरने वाले पर्यटकों के अलावा विवाह समारोहों, सामाजिक आयोजनों, व्यावसायिक बैठकों और मनोरंजन के लिए आने वाले लोगों को भी सुविधाएं मिल सकेंगी। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के कारण प्रयागराज में देश–विदेश से पर्यटकों और श्रद्धालुओं का आगमन होता है। ऐसे में आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी होटल की स्थापना से शहर की आतिथ्य क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। होटल के संचालन से रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ खानपान, परिवहन, इवेंट मैनेजमेंट, रिटेल और अन्य संबंधित व्यवसायों को भी लाभ मिल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार एफडीआई, एफसीआई और फॉर्च्यून कंपनियों के लिए निर्धारित निवेश प्रोत्साहन नीतियों के माध्यम से बड़े निवेशकों को प्रदेश में आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। इन दोनों प्रस्तावों की मंजूरी से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बल मिलने की उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा में औद्योगिक परियोजना और प्रयागराज में लग्जरी होटल का प्रस्ताव प्रदेश में निवेश के विविध क्षेत्रों के विस्तार को दर्शाता है। कुल १,९२५.९१ करोड़ रुपये के इन निवेश प्रस्तावों से औद्योगिक विकास, पर्यटन, आतिथ्य सेवाओं और संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है।

यूपी में ९२ हजार किमी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य, धीमी प्रगति पर पंचायती राज समेत कई विभागों को चेतावनी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने और उनके सु ढ़ीकरण अभियान में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक कर वित्तीय वर्ष २०२६–२७ के तहत सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही धीमी प्रगति वाले विभागों को चेतावनी देते हुए तत्काल कार्य में तेजी लाने को कहा। समीक्षा बैठक में २४ अक्टूबर २०२६ तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में कुल ६२,६७७.१० किलोमीटर सड़कों को गड्ढामुक्त करने और उनके नवीनीकरण का लक्ष्य निध ारित किया गया है। इसके सापेक्ष अब तक ५६,९०६.४३ किलोमीटर सड़कों पर काम पूरा हो चुका है, जो कुल लक्ष्य का ६१.४ प्रतिशत है। प्रमुख सचिव ने शेष कार्यों को बिना देरी पूरा करने और निध ारित लक्ष्य शत–प्रतिशत हासिल करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को ७७,३१४.६३ किलोमीटर सड़कों के कार्य का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष विभाग ने अब तक ५०,८८५.५९ किलोमीटर सड़कों का काम पूरा किया है, जो ६०.७१ प्रतिशत है। प्रमुख सचिव ने विभागीय अधिकारियों को शेष कार्यों में तेजी लाने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में कुछ कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति बेहतर पाई गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ६६.६४ प्रतिशत और पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ६७.१० प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। वहीं, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू, मोथ) ने ८५.०१ प्रतिशत और नगर विकास विभाग ने ७५.६४ प्रतिशत प्रगति दर्ज की है। प्रमुख सचिव ने इन विभागों के अधिकारियों से इसी गति को बनाए रखने की अपेक्षा की। समीक्षा में पंचायती राज विभाग की प्रगति महज ६.१० प्रतिशत सामने आई। मंडी परिषद ने २१.४० प्रतिशत और सिंचाई विभाग ने २५.३४ प्रतिशत कार्य पूरा किया है। इन विभागों की धीमी प्रगति पर प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने मैनपावर बढ़ाने, कार्यप्रणाली में सुधार करने और निर्धारित लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव अजय चौहान ने स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने वाली एजेंसियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने क्षेत्रीय और जिला स्तर के अधि ाकारियों को प्रतिदिन सड़कों का भौतिक निरीक्षण करने तथा दैनिक प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेशव्यापी गड्ढामुक्ति अभियान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का लक्ष्य सड़कों को बेहतर स्थिति में लाकर आवागमन को सुगम बनाना और आम जनता को राहत पहुंचाना है।

यूपी में १,७१० करोड़ का निवेश करेंगी चार कंपनियां, जीसीसी नीति के तहत योगी कैबिनेट की मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति–२०२४ के तहत चार औद्योगिक इकाइयों के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं के लिए कंपनियों को लेटर अ फ कम्फर्ट (एलओसी) जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चारों कंपनियां गौतमबुद्ध नगर में कुल १,७०६.८४ करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। इन परियोजनाओं से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के साथ अनुसंधान, नवाचार, तकनीकी विकास और वैश्विक व्यावसायिक संचालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि सरकार उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी उद्देश्य से जीसीसी नीति–२०२४ लागू की गई है, जिसके तहत वैश्विक कंपनियों को तकनीक, अनुसंधान, विकास और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रदेश में केंद्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रस्तावों के तहत हैवेल्स इंडिया लिमिटेड गौतमबुद्ध नगर में ८७६ करोड़ रुपये की लागत से



अत्याधुनिक अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र स्थापित करेगी। इस केंद्र में अनुसंधान और नवाचार से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं, एलजी स फ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ६३४ करोड़ रुपये के निवेश से ग्रीनफील्ड इको सॉल्यूशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य तकनीकी अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना है। अमेरिप्राइज इंडिया एलएलपी गौतमबुद्ध नगर में ११२.८४ करोड़ रुपये के निवेश से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेगी। इसके माध्यम से कंपनी की वैश्विक व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। दूसरी ओर, मेटलाइफ ग्लोबल अ परेशन्स सपोर्ट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड ऑक्सीजन बिजनेस पार्क में निजी भूमि पर ८४ करोड़ रुपये की लागत से एसटीपीई स्थापित करेगी। इस परियोजना के लिए भी लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी करने की मंजूरी दी गई है। औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि जीसीसी नीति–२०२४ का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया की प्रमुख कंपनियों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना है। सरकार निवेश के अनुकूल वातावरण तैयार करने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चारों परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षमताओं को मजबूती मिलने और वैश्विक कंपनियों की उपस्थिति बढ़ने की संभावना है। इससे उत्तर प्रदेश की तकनीकी एवं औद्योगिक पहचान को नई गति मिलने की उम्मीद है।

मान्यता प्राप्त पत्रकारों और परिजनों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा, आयुष्मान कार्ड के लिए नया पोर्टल होगा शुरू

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ा कराने की दिशा में नई पहल की गई है। इसके लिए आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB&PMJAY) के अंतर्गत विकसित नए पोर्टल को शुरू करने की सहमति दे दी गई है। सूचना परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविध ा का लाभ मिल सके। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला सूचना अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके आश्रितों के आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बने हैं, उनकी आवश्यक औपचारिकताएं एक सप्ताह के भीतर पूरी कराकर संबंधित विवरण पोर्टल



निदेशक विशाल सिंह की अध्यक्षता में सूचना निदेशालय के सभागार में आयोजित बैठक में पोर्टल की कार्यप्रणाली, आवेदन, सत्यापन और आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सूचना निदेशक ने पोर्टल को लाइव करने की सहमति प्रदान की। इसके बाद स्टेट हेल्थ एजेंसी के अधिकारियों ने पोर्टल की पूरी प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण किया। लाइव डेमो के माध्यम से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के आयुष्मान कार्ड जारी करने, आवेदन करने, दस्तावेजों के सत्यापन और कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया समझाई गई। इसमें सूचना निदेशालय मुख्यालय के साथ प्रदेश के सभी जिला सूचना कार्यालयों के अधि ाकारियों और कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। एक सप्ताह में पूरी करनी होगी प्रक्रिया सूचना निदेशक विशाल सिंह ने कहा कि पोर्टल को पत्रकारों के लिए सरल और सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि अधिक से अधि ाक मान्यता प्राप्त पत्रकारों और उनके पर अपलोड किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस कार्य की प्रगति से मुख्यालय को भी अवगत कराया जाए, जिससे मुख्यालय स्तर पर आगे की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जा सके। सूचना निदेशक ने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नए पोर्टल के माध्यम से आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। इससे पात्र पत्रकारों और उनके आश्रितों के आयुष्मान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। कार्ड जारी होने के बाद पात्र लाभार्थियों को निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल सकेगा। बैठक में वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी संजय कुमार सिंह, सहायक निदेशक सतीश चन्द्र भारती, डॉ. जितेन्द्र प्रताप सिंह, अमित कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

लखनऊ में तिहरे हत्याकांड के बाद कार्रवाई, सआदतगंज इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी निलंबित

लखनऊ। सआदतगंज थाना क्षेत्र के ब्राह्मणी टोला, नौबस्ता में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में फायरिंग के दौरान तीन लोगों की मौत के मामले में पुलिस विभाग ने कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त



तरुण गाबा ने सआदतगंज के थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार आर्य और कश्मीरी मोहल्ला चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक अजय कुमार चौरसिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। २६ अक्टूबर २०२६ को हुई इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी उठाई गई। परिजनों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग भी की। पुलिस के अनुसार, ब्राह्मणी टोला, नौबस्ता में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के दौरान फायरिंग हुई थी, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी को निलंबित करने का आदेश दिया। पुलिस के मुताबिक, फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल और चार खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। मामले में अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी जारी है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को उचित आर्थिक सहायता देने और आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। पुलिस विभाग की ओर से थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी का निलंबन किया गया है। हालांकि, निलंबन के विस्तृत कारणों और घटना से पहले पुलिस को किसी शिकायत की जानकारी थी या नहीं, इस संबंध में अलग से आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है।

कार पार्किंग विवाद में तीन लोगों की मौत के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा, मुआवजे और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में 112 जोड़ों ने लिए सात फेरे

लखीमपुर–खीरी। धौरहरा–ईसानगर ब्लाक में सोमवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में कुल ११२ जोड़ों का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न कराया गया। जानकारी के अनुसार ईसानगर ब्लाक में ५३ जोड़े, धौरहरा ब्लाक में ५८ जोड़े और नगर पंचायत में एक जोड़े का विवाह कराया गया। कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज धौरहरा में आयोजित किया गया। विवाह में सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी सुविधाएं दुल्हन को दी गईं। इसमें साड़ी, पेटीकोट, दुपट्टा चुनरी, पैंट शर्ट का कपड़ा, गमछा, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट, दीवार घड़ी, डबल बेड की चादर तकिया के साथ, गद्दा, तकिया, सिंघोरा, चूड़ियां और कंगन सहित कुल १५ सामान दिए गए। इस मौके पर विधायक विनोद शंकर अवस्थी, जिला समाज कल्याण



विभाग के अधिकारी, बीडीओ ईसानगर, बीडीओ धौरहरा सहित धौरहरा व ईसानगर के समस्त सचिव मौजूद रहे। अधिकारियों ने सभी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखी दांपत्य जीवन की कामना की।

इजरायल में टूटा मतदान का ४० साल का रिकॉर्ड

नई दिल्ली। इजरायल में मंगलवार दोपहर तक चार दशक से अधिक समय का सबसे ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। कड़े मुकाबले वाले संसदीय चुनाव में लाखों मतदाताओं के मतदान करने के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है। केंद्रीय चुनाव समिति के अनुसार, स्थानीय समयानुसार दोपहर दो बजे तक ४४.६ प्रतिशत पात्र मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके थे। वर्ष १९७३ के बाद इस समय तक दर्ज यह सबसे अधिक मतदान है। समिति ने बताया कि लगभग ७३ लाख पात्र मतदाताओं में से ३२,९०,४८० लोग मतदान कर चुके थे। मतदान बढ़ने से छोटी पार्टियों के लिए १२० सदस्यीय नेसेट (संसद) में सीट हासिल करने की चुनौती बढ़ सकती है। इजरायल में किसी पार्टी को सीटों के लिए पात्र होने हेतु ३.२५ प्रतिशत मत हासिल करना जरूरी है। कुल मतदान बढ़ने के साथ इस सीमा को पार करने के लिए जरूरी वोटों की संख्या भी बढ़ जाती है। इजरायली सेना के अनुसार, दोपहर एक बजे तक सैन्यकर्मियों में मतदान ४८ प्रतिशत रहा, जबकि २०२२ के चुनाव में इसी समय यह ४४.४ प्रतिशत था।



श्री नेतन्याहू और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट के बीच शुक्रवार को जारी जनमत सर्वेक्षणों में लगभग बराबरी का मुकाबला दिखाया गया था। किसी भी नेता के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी ६१ सीटें मिलने का अनुमान नहीं था। इससे सरकार गठन के लिए लंबी बातचीत की आशंका बढ़ गई है। चुनाव में सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं और श्री नेतन्याहू के नेतृत्व से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे हैं। मंगलवार सुबह कई दलों ने मतदान केंद्रों पर कथित अनियमितताओं की शिकायत की। हालांकि, केंद्रीय चुनाव समिति ने कहा कि मतपत्रों से व्यवस्थित छेड़छाड़ का कोई प्रमाण नहीं मिला है। नवगठित याशर पार्टी के नेता आइजेनकोट तथाकथित परिवर्तनवादी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें अलग–अलग विचारधाराओं वाले वे दल शामिल हैं जो नेतन्याहू को सत्ता में बने रहने से रोकना चाहते हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और एविग्दोर लिबरमैन जैसे दक्षिणपंथी नेता शामिल हैं, जो सुरक्षा के मुद्दों पर कड़ा रुख रखते हैं। वहीं, पूर्व जनरल यायर गोलान वामपंथी विचारधारा से जुड़े हैं। पहली बार १९९६ में प्रधानमंत्री बने श्री नेतन्याहू अपनी मौजूदा सरकार में शामिल धुर दक्षिणपंथी और अति–रूढ़िवादी यहूदी दलों के साथ गठबंधन के जरिए एक और कार्यकाल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी अभियान में सात अक्टूबर २०२३ को हमास के नेतृत्व में हुए हमलों से पहले की सुरक्षा संबंधी विफलताएं प्रमुख मुद्दा रही हैं। उन हमलों में लगभग १,२०० लोग मारे गए थे और २५१ लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था। विपक्षी नेताओं ने स्वतंत्र जांच आयोग गठित करने की मांग की है, जिसका श्री नेतन्याहू विरोध करते रहे हैं। उनका तर्क है कि ऐसी जांच उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण होगी। विपक्ष ने उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे और विवादित न्यायिक सुधारों की कोशिशों की भी आलोचना की है। श्री नेतन्याहू आरोपों से इनकार करते हैं। सात अक्टूबर के हमलों से पहले न्यायिक सुधारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। श्री नेतन्याहू ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए क्षेत्रीय संघर्षों में अपनी सरकार की रणनीतिक सफलताओं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने करीबी संबंधों को रेखांकित किया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में खबरें आईं कि श्री नेतन्याहू ने मतदान से पहले ईरान के खिलाफ नई सैन्य कार्रवाई के लिए मंजूरी मांगी थी। इजरायल के चौनल १२ ने बताया कि सेना प्रमुख एयाल जमीर ने इस कदम का विरोध किया था। इसके बाद सीएनएन ने खबर दी कि श्री नेतन्याहू ने ट्रंप को नए हमलों की मंजूरी देने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया गया। श्री नेतन्याहू ने दोनों खबरों का खंडन किया है।

चुनावी हार के बाद फ्लावियो बोल्सोनारो के विदेश जाने पर रोक

नई दिल्ली। ब्राजील में राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से हार के बाद दक्षिणपंथी नेता फ्लावियो बोल्सोनारो के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गयी है और उन्हें अपने सभी पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने जारी किया। उन्होंने फ्लावियो के पिता और पूर्व राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के खिलाफ कथित तख्तापलट की कोशिश से जुड़े मुकदमे की भी सुनवाई की थी। श्री बोल्सोनारो ने सोशल मीडिया पर साझा एक वीडियो में बताया कि वह ब्रासीलिया में नजरबंद अपने पिता से मिलकर लौटे थे, तभी संघीय पुलिस ने उन्हें आदेश सौंपा। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई उनके भाई एडुआर्डो बोल्सोनारो के शुक्रवार को एक अमेरिकी प डकास्ट में दिये गये साक्षात्कार के आधार पर की गयी, जिसमें एडुआर्डो ने चुनाव हारने की स्थिति में उन्हें ब्राजील छोड़ने की सलाह दी थी। श्री बोल्सोनारो ने कहा मैंने ऐसा कभी नहीं कहा," और देश छोड़ने की कोई मंशा जाहिर करने से इनकार किया। अदालत का आदेश धनशोधन की एक कथित योजना में फ्लावियो की संभावित भूमिका की आपराधिक जांच से जुड़ा है। इसमें उन्हें अपने मित्र और वकील विलर तोमाज से संपर्क करने से भी रोक दिया गया है। तोमाज का संबंध उन सट्टेबाजी कंपनियों से बताया गया है, जिनका इस्तेमाल पुलिस को लगभग ६८ करोड़ पाउंड की धनराशि के कथित धनशोधन में किए जाने का संदेह है। अदालत ने श्री बोल्सोनारो के सभी पासपोर्ट रद्द कर दिये हैं। इनमें सांसद के रूप में मिला उनका राजनयिक पासपोर्ट भी शामिल है। उन्हें २४ घंटे के भीतर सभी पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। श्री बोल्सोनारो की पार्टी ने सोमवार रात जारी बयान में चुनाव परिणाम स्वीकार किया। बयान में कहा गया, "हम चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा घोषित राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि उठाए गए सवालों को संतुलित और लोकतांत्रिक राजनीतिक बहस के जरिए उचित रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।" श्री बोल्सोनारो ने अपने पिता की



तरह, जो चार साल पहले पिछले राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद भी परिणाम स्वीकार नहीं कर पाये थे, लूला के हाथों अपनी हार स्वीकार नहीं की है। समाचार पत्र 'फोल्हा डी साओ पाउलो' के अनुसार, सहयोगियों और वकीलों ने श्री बोल्सोनारो को चुनाव रद्द कराने की मांग छोड़ने के लिए मनाया। उन्होंने रविवार रात यह मांग की थी। उनका तर्क था कि अनिवार्य मुफ्त सार्वजनिक परिवहन तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करने वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान का समय दो घंटे बढ़ाये जाने से चुनाव प्रभावित हुआ। हालांकि, उनके अपने चुनाव अभियान ने भी मतदान का समय बढ़ाने की मांग की थी। अखबार के मुताबिक, सलाहकारों ने उन्हें बताया कि इस संबंध में कानूनी दलील कमजोर है। श्री बोल्सोनारो ने सार्वजनिक रूप से चुनाव रद्द करने की मांग वापस नहीं ली है। उन्होंने वीडियो में कहा कि वह लूला के राष्ट्रपति चुनाव में उतरे गठबंधन को कथित तौर पर आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग के आधार पर अयोग्य ठहराने के लिए अलग मुकदमा दायर करेंगे। श्री बोल्सोनारो एक अन्य जांच का भी सामना कर रहे हैं। यह मामला उनके उस कथित अनुरोध से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपी एक बदनाम बैंकर से अपने पिता पर बनने वाली जीवनीपरक फिल्म के लिए लगभग दो करोड़ पाउंड की व्यवस्था करने को कहा था। बताया गया है कि इस बातचीत की रिक डिंग भी हुई थी। श्री बोल्सोनारो का सीनेट सदस्य के रूप में कार्यकाल अगले साल की शुरुआत में समाप्त होने वाला है। पद छोड़ने के बाद उन्हें जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला विशेष कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। वह पिछले २४ वर्षों से सार्वजनिक पद पर रहे हैं।

रामलीला मेले के लिए हुआ धूमधाम से धरती पूजन

तिकुनिया खीरी। कस्बे मे श्री जनता रामलीला कमेटी द्वारा ७६ वा वार्षिक उत्सव के लिए रामलीला मैदान में धूमधाम से भूमि पूजन किया गया पंडित हेमंत शर्मा द्वारा वैदिक मन्त्रों से पूजा अर्चना कराई गई है इस अवसर पर श्री जनता रामलीला कमेटी के मुख्य अतिथि सुथना देवी मंदिर के महंत बाबा बृजेश गिरी सहित गणमान लोग मौजूद रहे सोमवार को करीब २रू०० बजे निर्धारित कार्यक्रम के तहत श्री जनता रामलीला कमेटी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता उर्फ नीटू गुप्ता से पुरोहित हेमंत शर्मा ने पूजा अर्चना कराई है इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष ने कहा इस बार २६ अक्टूबर दिन सोमवार से १० नवंबर मंगलवार तक मेला चलेगा पारंपरिक रूप से लगने वाला रामलीला मेला क्षेत्र की जनता के सहयोग से संपन्न होता आ रहा है जिसमें भारत नेपाल के नागरिकों की भागीदारी भारी संख्या में होती है मेले में आने वाले सभी दुकानदार भाइयों से अपील है की अपनी दुकान समय पर आकर मेले में जगह लेकर लगा ले मेले में इस बार चिकित्सा सुविधा की भी व्यवस्था कराई जाएगी इसके अलावा कवि सम्मेलन राष्ट्रीय कवियों के द्वारा संपन्न होगा इस अवसर पर कमेटी के महामंत्री अजय गर्ग टीटू, कोषाध्यक्ष शिशिर गुप्ता, संरक्षक शिव कुमार गर्ग चेयरमैन कार्यवाहक उपाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुज गुप्ता, पूर्व प्रधान विनायक प्रसादें,ष्णासिंह बाबू, किशन महावर, पदम अग्रवाल, सुरेश अग्रवाल, पप्पू सोनी, आशीष गर्ग रमेश गर्ग,अनिल कुंबले, एडवोकेट जितेंद्र कुमार, जगदीश प्रसाद ,उमेश निषाद, पत्रकार रूप नारायण मिश्रा, लवकुश कुमार, पप्पू सिंह, रामगोपाल, यज्ञदेव मिश्रा, संदीप कुमार, सतीश कुमार मौजूद रहे।

पश्चिम–मध्य बंगाल की खाड़ी में गहराया 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' अर्नब

नई दिल्ली। मौसम विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'अर्नब' बेहद तेजी से और मजबूत होकर 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान' में तब्दील हो गया है। इस कारण कई तटीय इलाकों में आज (२७ अक्टूबर) और २८ अक्टूबर को भारी से भारी बारिश का अनुमान लगाया गया हे। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा तटों के लिए 'रेड अलर्ट ' जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, २६ अक्टूबर की शाम को यह चक्रवात 'गंभीर चक्रवाती तूफान' की श्रेणी पहुंच गया था और आधी रात में यह 'अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान'में तब्दील हो गया। मंगलवार २७ अक्टूबर को सुबह साढ़े आठ बजे यह विशाखापत्तनम से लगभग



२२० किमी दक्षिण–दक्षिण पूर्व में केंद्रित था। मौसम विभाग का अनुमान है कि अर्नब २७ अक्टूबर की शाम तक पश्चिम–उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और इसके बाद, यह उत्तर–पश्चिम दिशा में मुड़ेगा। यह बुधवार २८ अक्टूबर की सुबह/पूर्वाह्न तक इसके बापटला और विशाखापत्तनम के बीच, यानम के पास एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश तथा यानम तटों को पार करने की संभावना है। तट से टकराते समय हवा की अधिकतम रफ्तार १२५ से १३५ किमी प्रति घंटे रहने और बढ़कर १५० किमी प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। चक्रवात 'अर्नब' पर विशाखापत्तनम स्थित डॉपलर वेदर रडार से लगातार नजर रखी जा रही है।

ज्ञानेश हटें, आंदोलन तुरंत रुकेगा

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटा दें तो विपक्ष का आंदोलन ३० सेकंड में रुक जाएगा। उन्होंने दिल्ली के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक्स पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस उनकी बात सुन रही है और उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मेट्रो बंद की, सड़कें सील कीं और राजधानी पर ताला लगाया। राहुल ने दावा किया कि जब वोट ही चोरी हो जाए तो किसी की दुकान, बचत और बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को 'आरोपी नंबर चार' कहा। हालांकि, पोस्ट में यह स्पष्ट नहीं किया कि इस संबोधन का आधार क्या है। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने कथित वोट चोरी के खिलाफ एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली बुलाई है। चौंबर अ फ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने



राहुल को पत्र लिखकर रैली के समय पर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि धनतेरस और दिवाली से पहले बाजारों में बड़ी संख्या में ग्राहक आते हैं। ऐसे समय रैली से आसपास के थोक और खुदरा बाजारों का कारोबार प्रभावित हो सकता है।

'नल पर पानी पीने गई महिला पर तेंदुए का हमला, गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर रेफर'

'मैलानी खीरी' मैलानी थाना क्षेत्र के ग्राम नारंग खुड्डी में मंगलवार तड़के घर के बाहर लगे नल पर पानी पीने गई ६२ वर्षीय महिला पर हिंसक वन्यजीव ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शोर सुनकर ग्रामीण मौके पर जुटे तो वन्यजीव महिला को छोड़कर भाग निकला। वन विभाग के अनुसार, घटनास्थल के आसपास तेंदुए के पगचिह्न मिले हैं। जानकारी के मुताबिक, ग्राम नारंग खुड्डी निवासी कौशल्या देवी (६२), पत्नी राम नरेश, मंगलवार तड़के करीब तीन बजे घर के बाहर लगे नल पर पानी पीने गई थीं। इसी दौरान नल के पास बैठे वन्यजीव ने अचानक उन पर हमला कर दिया। महिला की चीख–पुकार सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों की भीड़ जुटने पर वन्यजीव महिला को छोड़कर भाग गया। हमले में गंभीर रूप से घायल कौशल्या देवी को परिजनों और ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल लखीमपुर के ट्रामा सेंटर भेजा गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने घर के आसपास तेंदुए के पगचिह्न मिलने की पुष्टि की है। इससे ग्रामीणों में जंगली जानवर की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ गई है।

'विकलांग छात्रो को कराया गया भ्रमण'

लखीमपुर खीरी। समग्र शिक्षा अभियान समेकित शिक्षा के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को सुगम्य, प्रेरणादायक विद्यार्थीपरक वातावरण हेतु ५० जो विभिन्न दिव्यांगता वाले बच्चे सम्मलित किए गए साथ ही कराया गया,जिसमें बच्चों को वहां पर के के बारे जानकारी दी गई। यह भ्रमण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी के दिशा निर्देशों और जिला समन्वयक समेकित शिक्षा श्रीमती माला श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में पूरा किया



इनकी देख रेख के लिए दो केयर टेकर(एक पुरुष और एक महिला)के साथ एक्सपोजर विजिट कौड़ियाला घाट निघासन ले जाया गया। इसमें विकास क्षेत्र ईसानगर, धौरहरा, रमियाबेहड, निघासन व पलिया के बच्चों को कौड़ियाला घाट गुरुद्वारा आदि स्थान पर बच्चों को भ्रमण गया। साथ ही इस भ्रमण में विशेष शिक्षक प्रहलाद कुमार,विवेक त्रिपाठी लालजी, विजय शंकर चौधरी, नरेश कुमार गुप्ता,सुशील पटेल,सरोज,विनय शुक्ला,शिवभान मौर्य संदीप कुमार, ब्रजेंद्र त्रिपाठी,नरेंद्र कुमार यादव पंकज कुमार आदि ने सहयोग किया।

देववाणी मंत्रों और काव्यधारा से गूंजा ऐतिहासिक दशहरा मेला चतुर्थ दिवस

लखीमपुर–खीरी। भारतीय संस्कृति की सनातन चेतना, साहित्य की गरिमा और देववाणी संस्कृत की मधुर काव्यधारा से लखीमपुर का ऐतिहासिक दशहरा मेला चौथे दिन सराबोर हो उठा। संस्कृत कवि सम्मेलन में श्लोकों और



काव्यात्मक अभिव्यक्तियों ने वातावरण को आध्यात्मिक एवं साहित्यिक गरिमा से आलोकित कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि धौरहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, विशिष्ट अतिथि ब्ल क प्रमुख दिव्या सिंह, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉ. इरा श्रीवास्तव तथा अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन सत्र का संचालन समाजसेवी एवं साहित्यकार राममोहन गुप्त 'अमर' ने किया। इस अवसर पर समाजसेवा में उल्लेखनीय योगदान के लिए युवराजदत्त महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ. डी. एन. मालपानी, संघ के सेवा प्रमुख आनंद अवस्थी तथा प्रमोद कुमार शर्मा को समाजसेवी सम्मान से विभूषित किया गया। कार्यक्रम के संयोजन में बृजेश पाल, राकेश कुमार, अनिरुद्ध त्रिपाठी, अजय अग्रवाल और सुरेन्द्र पाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अवसर पर मेलाधिकारी समरा सईद, मेला अध्यक्ष रवींद्र रावत, सह अध्यक्ष नीलम रस्तोगी, शमीम बानो, इंजीनियर दुर्गेश वर्मा, राजकुमार त्रिवेदी, संजय त्रिवेदी, पं ओंकार नारायण दुबे, आचार्य पंकज कृष्ण शास्त्री, आचार्य संजय मिश्रा, सुरचना त्रिवेदी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान संस्कृत विद्यालय के बच्चों ने खूबसूरत प्रस्तुति भी दी। संस्कृत भारती अवध प्रांत द्वारा संस्कृत कवि सम्मेलन ने संदेश दिया कि अपनी प्राचीन भाषायी विरासत का संरक्षण और समाजसेवियों का सम्मान ही सांस्कृतिक चेतना को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है।

दशहरा मेला में जेसीआई ने स्मृति स्तंभ पर श्रंद्धाजलि सभा आयोजित की

लखीमपुर खीरी। नगर की सुपरिचित समाजसेवी संस्था जेसीआई लखीमपुर खीरी ने मेला परिसर में बने स्मृति स्तंभ पर श्रंद्धाजलि सभा आयोजित कर १९७६में आये भीषण तूफान में हताहत हुये जनमानस के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किये। दो मिनट का मौन रख कर व मोमबत्ती जलाकर कर अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। ज्ञातव्य है कि उस त्रासदी हेतु जेसीआई द्वारा एक स्मृति स्तंभ का निर्माण करवाया गया था और तबसे प्रत्येक वर्ष दशहरा मेला के दौरान संस्था सदस्य अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम निदेशक आलोक शुक्ला, प्रभारी राजेश पटेल, आगामी अध्यक्ष विश्वास सेठ के साथ सचिन अग्रवाल, विशाल सेठ, राममोहन गुप्ता, सुमित शर्मा, कुशाग्र अग्रवाल, राहुल माथुर, लव पुरी, अनिल अग्रवाल, कनिष्क बरनवाल, शुभम टण्डन, कुमार उत्कर्ष, सौरभ गुप्ता, लेखनी सेठ, मंजू बरनवाल, मुक्ति अग्रवाल, पारुल पटेल, समीक्षा टण्डन आदि मौजूद रहे। उक्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी आर्येन्द्र पाल सिंह ने बताया कि संस्था की चली आ रही परम्परा के अनुसार आगामी अध्यक्ष अपने कार्यकाल का शुभारंभ इस कार्यक्रम के साथ करता है और पारिवारिक मेला भ्रमण भी करवाता है।

देश के 22ः खाद्यान्न का उत्पादन करता है यूपी, 10 लाख किसानों को मुफ्त मिलेंगे दलहन–तिलहन के उन्नत बीज

लखनऊ। उत्तर प्रदेश देश की मात्र ११ प्रतिशत कृषि योग्य भूमि पर लगभग २२ प्रतिशत खाद्यान्न का उत्पादन कर रहा है। प्रदेश में फसल सघनता बढ़कर १९६ प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह बात कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मंगलवार को आईसीएआर–भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद (उपकार) के ३७वें स्थापना दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में कही। संगोष्ठी का विषय 'उत्पादकता से आगेः उत्तर प्रदेश की ेंषि के भविष्य की पुनर्कल्पना' था। कृषि मंत्री ने कहा कि बढ़ती आबादी की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि आवश्यक है। भारत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ८० करोड़ नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सक्षम है। ऐसे में राष्ट्रीय और वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश का लगभग ८० प्रतिशत कृषि क्षेत्र सिंचित हो चुका है। नहरों के विस्तृत नेटवर्क से किसानों को खरीफ के साथ रबी और जायद की फसलों के लिए भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की उत्पादन लागत घटाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि चालू रबी सत्र में किसानों को १२ लाख क्विंटल प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह मात्रा पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान उपलब्ध कराए जाने वाले



चार लाख क्विंटल बीज के मुकाबले तीन गुना है। इसके अतिरिक्त गेहूं और गन्ने की पारंपरिक खेती पर निर्भरता कम करने तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए १० लाख किसानों को दलहन और तिलहन के उन्नत बीजों की मिनीकिट मुफ्त वितरित की जा रही हैं। कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों से बाजार की मांग और अधिक मूल्य देने वाली फसलों पर अनुसंधान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए नई तकनीकों और उन्नत किस्मों का विकास जरूरी है। मौसम की अनिश्चितताओं और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए उन्होंने उपकार तथा कृषि विश्वविद्यालयों को कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों की किस्में और आपातकालीन फसल प्रबंधन तकनीकें तेजी से किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। मृदा में अ र्गेनिक कार्बन की घटती मात्रा पर चिंता जताते हुए उन्होंने गोबर, गोमूत्र और बायोमास आधारित प्रों तिक खेती को जन–आंदोलन बनाने पर बल दिया। धान कटाई के मौसम को देखते हुए मंत्री ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग ६०० कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से पराली और कृषि अवशेषों का उपयोग बायो–सीएनजी, कम्पोस्ट और मल्चिंग के लिए किया जा सकेगा। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में महिला किसानों तथा ग्रामीण युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता भी बताई। समारोह में कृषि अनुसंधान, तकनीकी प्रसार और नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वैज्ञानिकों, संस्थानों और किसानों को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट वैज्ञानिकों में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के प्रसार निदेशक डॉ. राम बटुक सिंह और बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशक डॉ. एन.के. बाजपेई शामिल रहे। उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए नौ कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को सम्मानित किया गया। इनमें मेरठ के रामपुर एवं हस्तिनापुर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बरकछा (मिर्जापुर), बांदा कृषि विश्वविद्यालय के बांदा, महोबा एवं झांसी, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के कानपुर देहात एवं फतेहपुर तथा आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के जौनपुर प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र शामिल हैं। फसल विविधीकरण और नवाचार के लिए सात प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। इनमें सिद्धार्थनगर के सुधीश नाथ शुक्ला को काला नमक धान, गाजीपुर के अमरजीत सिंह को सीधी बिजाई, बहराइच के बुधई को मक्का बीज उत्पादन, मिर्जापुर की वंदना सिंह को ड्रैगन फ्रूट एवं स्ट्रॉबेरी की खेती, सहारनपुर के राजेंद्र पुंडीर को संरक्षित खेती एवं मत्स्य पालन, सीतापुर की सीता देवी को अपराजिता की औषधीय खेती और बहराइच के जियाउल हक को संकर मक्का बीज उत्पादन के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा उपकार के वैज्ञानिक डॉ. रिन्नी सिंह, डॉ. हिमांशु तिवारी और प्रेमचंद चौरसिया को भी उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपकार के अध्यक्ष कैप्टन विकास गुप्ता ने की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता, बीज प्रमाणीकरण संस्था के उपाध्यक्ष राध ेश्याम सिंह, कृषि एवं अनुसंधान विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एम.के. शनमुगा सुंदरम, उपकार के महानिदेशक डॉ. संजय कुमार, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. एस.एन. सुशील सहित विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, वैज्ञानिक, कृषि प्रसार कार्यकर्ता, किसान और एफपीओ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

योगी कैबिनेट का बड़ा फैसलाः यूपी के १.७० लाख से अधिक शिक्षा कर्मचारियों को मिलेगा ५ लाख तक कैशलेस इलाज, आश्रित भी होंगे लाभान्वित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कैशलेस चिकित्सा सुविध ा देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के तहत माध यमिक, वित्तविहीन और संर्स्ेत विद्यालयों के ४८,०६२ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के १,२२,३०५ कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक बोझ से राहत देना है। पात्र कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की कैशलेस सुविधा मिलेगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के २३,६८६, वित्तविहीन विद्यालयों के २२,५४१ और अशासकीय सहायता प्राप्त संर्स्ेत विद्यालयों के करीब ११० शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस तरह कुल ४८,०६२ कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। सरकार प्रत्येक कर्मचारी



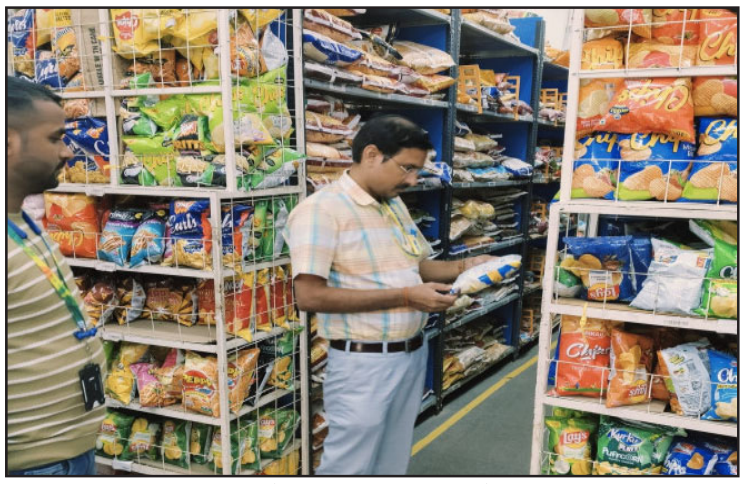
के बीमा प्रीमियम के लिए ३,००० रुपये देगी। इस मद में कुल १४.४१ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस सुविधा के तहत पात्र कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को पांच लाख रुपये तक के इलाज की कैशलेस सुविधा उपलब्ध होगी। कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों के लिए भी कैशलेस चिकित्सा सुविध ा के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, इस फैसले से १,२२,३०५ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक, वित्तविहीन संस्थानों के कर्मचारी और जिला परियोजना से जुड़े कर्मी शामिल हैं। सरकार के इस निर्णय से पात्र कर्मचारियों और उनके आश्रितों को इलाज के खर्च की चिंता से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कैशलेस इलाज की सुविधा किन अस्पतालों में और किन शर्तों के तहत मिलेगी, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित शासनादेश और दिशा–निर्देश जारी होने के बाद स्पष्ट होगी। यूपी में शिक्षा क्षेत्र के १.७० लाख से अधिक कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया, पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक इलाज का लाभ मिलेगा।

बेटी ने पिता को पहले खिलाई नींद की गोलियां, फिर प्रेमी के साथ मिलकर पिता को मार डाला

इटावा। जिले की पुलिस ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी १७ वर्षीय बेटी को हिरासत में लिया है और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, किशोरी ने कथित तौर पर प्रेमी के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से अपने पिता श्याम सुंदर कठेरिया को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया और फिर चाकू से उनका गला काट दिया। इसके बाद सिल–बट्टे से वार कर उनका सिर और चेहरा कुचल दिया। इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों ने शव को कंबल में लपेटकर एक संदूक में रख दिया और घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में टीबी अस्पताल के पास स्थित कांशीराम क लोनी के निवासी श्याम सुंदर की हत्या यह मामला २५ अक्टूबर को सामने आया, जब उनकी बड़ी बेटी काजल कठेरिया ने पुलिस से संपर्क किया। उसने पुलिस को बताया कि वह पिछले दो–तीन दिनों से अपने पिता और छोटी बहन से संपर्क नहीं कर पा रही है। पुलिस ने बताया कि जब काजल अपने ससुर के साथ मायके पहुंची, तो घर से दुर्गंध आ रही थी। घर के अंदर एक संदूक में उसके पिता का शव कंबल में लिपटा हुआ मिला, जबकि उसकी छोटी बहन वहां मौजूद नहीं थी। पुलिस ने बताया कि इसके बाद इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। सिविल लाइंस के थाना प्रभारी केके मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस दल ने फ रेंसिक विशेषज्ञों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवा दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि शुरुआती जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सराय असर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर किशोरी और उसके प्रेमी अभिलाष सिंह को पकड़ लिया। अभिलाष इसी क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने कहा, ''पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनकी मुलाकात करीब पांच महीने पहले हुई थी। उस समय किशोरी ने मोबाइल फोन में रिचार्ज कराने के लिए अभिलाष को अपना फोन नंबर दिया था। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू होने लगी।'' पुलिस के मुताबिक, श्याम सुंदर को जब इस संबंध के बारे में पता चला, तो उन्होंने शुरुआत में अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की लेकिन किशोरी ने संबंध खत्म करने से इनकार कर दिया।

लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा और नोएडा समेत विभिन्न जनपदों में खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष जांच'

लखनऊ। प्रदेश में अ नलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए घरों तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने खाद्य सुरक्षा निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स पर प्रदेशव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान चलाकर खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की व्यापक पड़ताल की। ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन, रिलायंस और मेट्रो सहित विभिन्न प्लेटफ र्म से जुड़े प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छता, तापमान नियंत्रण, कोल्ड स्टोरेज, वैधता अवधि, लेबलिंग और लाइसेंस संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की गई। अभियान के दौरान कुल २१८ प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर अनियमितताओं पर कार्रवाई की गई। मानकों में कमियां मिलने पर १५४ सुधार नोटिस जारी किए गए, ६ स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर सुधार होने तक कारोबार बंद कराया गया और जांच के लिए ११ खाद्य नमूने संग्रहित किए गए। इसके अलावा दो स्टोर्स में फ्रोजन मीट एवं मीट उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई, जबकि आगरा में लेबल संबंधी अनियमितताओं के चलते मखाने के २७३ पैकेट, जिनका अनुमानित मूल्य ६८ हजार रुपये है, सीज किए गए। गाजियाबाद में आरडीएल के निकट स्थित जेप्टो वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान साफ–सफाई में गंभीर कमियां सामने आईं। परिसर में अत्यधिक गंदगी, दीवारों पर जाले,



क्षतिग्रस्त फर्श और क करोच पाए गए। खाद्य पदार्थों के भंडारण स्थल पर इस प्रकार की स्थितियां खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों के अनुरूप नहीं हैं। विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रतिष्ठान के लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई की। कानपुर नगर में रिलायंस मार्ट, मेट्रो और जेप्टो स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। इस दौरान लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप नियंत्रित वातावरण और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था में कमियां पाई गईं। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों के भंडारण और लेबलिंग से जुड़े प्रावधानों की जांच में भी अनियमितताएं सामने आईं। कुछ खाद्य उत्पादों पर बेस्ट बिफोर संबंधी निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया गया। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों को नियमों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए सुधार होने तक कारोबार बंद कराने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अ नलाइन अ र्डर के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थ निर्धारित परिस्थितियों में सुरक्षित रखे जाएं और उनकी गुणवत्ता से समझौता न हो। आगरा में रिलायंस स्टोर के निरीक्षण के दौरान राय लाइज ब्रांड के मखाने के २७३ पैकेटों में लेबल संबंधी अनियमितताएं पाई गईं। विभाग ने इन पैकेटों को सीज कर दिया। जब्त खाद्य पदार्थों का अनुमानित मूल्य लगभग ६८,००० रुपये बताया गया है। संबंधित प्रतिष्ठान को आवश्यक सुधार करने के लिए नोटिस भी जारी किया गया। इस कार्रवाई के माध्यम से विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य उत्पादों की बिक्री में लेबलिंग और नियामकीय प्रावधानों का पालन आवश्यक है। अ नलाइन या अ फलाइन, किसी भी माध्यम से खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कारोबारियों को निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। लखनऊ में चिनहट स्थित जेप्टो स्टोर के निरीक्षण में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। स्टोर में गंदगी, कीटों की मौजूदगी, जंग और फफूंदयुक्त रैक पाए गए। इसके अलावा खाद्य पदार्थों को दवाओं एवं न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ रखा जा रहा था। भंडारण की इस व्यवस्था को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने संबंधित स्टोर का लाइसेंस निलंबित कर सुधार होने तक कारोबार बंद करा दिया। वहीं, चिरैयाबाग स्थित जेप्टो और हुसैनाबाद स्थित ब्लिंकिट स्टोर में लाइसेंस पर आवश्यक अनुमोदन के बिना मीट एवं मीट उत्पादों की बिक्री किए जाने का मामला सामने आया। विभाग ने संबंधित प्रतिष्ठानों में ऐसी बिक्री तत्काल बंद करा दी। गौतमबुद्धनगर के वाजिदपुर, सेक्टर–१३५ स्थित जेप्टो स्टोर के निरीक्षण में जंग और फफूंदयुक्त रैक, क्षतिग्रस्त एवं गंदे कोल्ड रूम तथा फर्श पर बिखरे खाद्य पदार्थ पाए गए। खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण के लिहाज से इन कमियों को गंभीर माना गया। विभाग ने आवश्यक सुधार होने तक संबंधित कोल्ड रूम में खाद्य कारोबार बंद करा दिया और वहां रखे खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी। इस कार्रवाई के जरिए कोल्ड चेन और भंडारण की स्वच्छता को खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हुए निर्धारित मानकों के अनुपालन पर जोर दिया गया। 'शुद्ध ही शुभ है' अभियान के तहत की गई यह कार्रवाई इस बात पर केंद्रित है कि ई–क मर्स प्लेटफॉर्म और डार्क स्टोर्स के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थ गुणवत्ता, स्वच्छता और सुरक्षित भंडारण के निर्धारित मानकों पर खरे उतरें। अ नलाइन ऑर्डर की बढ़ती लोकप्रियता के बीच वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स में तापमान नियंत्रण, कोल्ड स्टोरेज, कीट नियंत्रण, साफ–सफाई, लेबलिंग और वैधता अवधि की निगरानी महत्वपूर्ण हो गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का उद्देश्य केवल अनियमितताओं की पहचान करना ही नहीं, बल्कि संबंधित कारोबारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुधारने के लिए बाध्य करना भी है। गंभीर कमियां पाए जाने पर लाइसेंस निलंबन, कारोबार बंद कराने, खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक और उत्पादों को सीज करने जैसी कार्रवाई की जा रही है।

किसान पथ पर फॉर्मलीन से भरा टैंकर पलटा, २ किमी तक फैली जहरीली भापय आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत से मचा हड़कंप

लखनऊ लखनऊ के बख्शी का तालाब इलाके में किसान पथ पर सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया। फॉर्मलीन रसायन से भरा



एक तेज रफ्तार टैंकर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। टैंकर पलटते ही उससे जहरीले केमिकल का रिसाव (लीकेज) शुरू हो गया, जिससे देखते ही देखते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। केमिकल की जहरीली भाप हवा में घुलते ही लगभग २ किलोमीटर के दायरे में दहशत फैल गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों और आसपास के बाशिंदों की आंखों में तेज जलन होने लगी और सांस लेना तक मुश्किल हो गया। मामला बिगड़ता देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एहतियातन बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को दोनों तरफ से बंद कर दिया और गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी। आपको बता दें कि फार्मलीन दरअसल श्फ र्मल्डिहाइडश का पानी में घोल होता है। इसका इस्तेमाल मेडिकल लैब में सैंपल सुरक्षित रखने और कई फैक्ट्रियों में किया जाता है। इससे निकलने वाले वाष्प (गैस) सीधे आंखों, नाक और गले पर हमला बोलते हैं। अगर कोई इंसान ज्यादा देर तक इसके संपर्क में रहे, तो उसे तेज खांसी, सांस का संकट और फेफड़ों को हमेशा के लिए गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। फिलहाल टैंकर किन हालातों में पलटा, उसमें कितना केमिकल भरा था और कितने लोग इसकी जद में आए हैं, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। हवा में जहर के असर की जांच के बाद ही सही स्थिति का पता चलेगा। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. जेपी सिंह ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि ऐसे केमिकल रिसाव की स्थिति में सबसे पहला काम उस जगह से दूर किसी सुरक्षित जगह जाना है। बिना किसी सुरक्षा किट या मास्क के टैंकर के पास जाना या केमिकल साफ करने की कोशिश करना जानलेवा हो सकता है। अगर किसी को भी आंखों में जलन, गले में खराश या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो बिना देर किए तुरंत ड क्टरी मदद लें।

लखनऊ में आज से सजेगा माटीकला महोत्सव-२०२६, मंत्री राकेश सचान करेंगे उद्घाटन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड की ओर से राजधानी लखनऊ में २८ अक्टूबर से ७ नवंबर २०२६ तक माटीकला महोत्सव–२०२६ का आयोजन किया जा रहा है। पारंपरिक शिल्पकारों को मंच उपलब्ध कराने और माटीकला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस ११ दिवसीय महोत्सव की थीम 'मिट्टी से संस्कृति, संस्कृति से समृद्धि' रखी गई है। महोत्सव के तहत माटीकला उत्पादों की राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन बुधवार, २८ अक्टूबर को शाम पांच बजे खादी भवन प्रांगण, ८–तिलक मार्ग, डालीबाग, लखनऊ में होगा। प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान मुख्य अतिथि के रूप में प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर भी उपस्थित रहेंगे। महोत्सव में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए कुशल शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए उत्कृष्ट माटीकला उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके माध्यम से पारंपरिक कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और उन्हें आम लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। साथ ही, मिट्टी से बने पारंपरिक एवं कलात्मक उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ाने और स्थानीय शिल्प को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के मुख्य कार्यपालक



अधिकारी शिशिर ने नागरिकों, कला प्रेमियों और गणमान्य लोगों से महोत्सव में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने लोगों से खादी भवन प्रांगण पहुंचकर शिल्पकारों के उत्पादों का अवलोकन करने और उनके हुनर को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया है। महोत्सव का उद्देश्य पारंपरिक माटीकला को नई पहचान दिलाने के साथ स्थानीय कारीगरों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और प्रदेश की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को आगे बढ़ाना है।

अखिलेश यादव ने निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, बोलेंमतदाता सूची को आधार से जोड़ें और बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करें

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए चुनाव में हेरफेर की साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ने और बायोमेट्रिक सत्यापन लागू करने की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से अधिकारियों के खिलाफ हाल में की गई कार्रवाई से उनकी पार्टी की चिंताएं दूर नहीं होंगी। उन्होंने आगामी चुनावों के मद्देनजर लगातार सतर्क रहने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ष्अब निर्वाचन आयोग जागा है और अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हमें इससे तसल्ली नहीं मिलेगी, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। क्या इन छोटी कार्रवाइयों के पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं? वरना बाद में हम यही कहते रह जाएंगे कि देखिए, क्या हो गया।' उन्होंने हालिया विधान परिषद चुनावों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया, षविधान परिषद चुनावों की मतगणना के दौरान मतपेटियों के अंदर बिना मुड़े हुए मतपत्र कैसे मिल सकते हैं? क्या किसी ने सोचा भी होगा कि मतपेटियों के अंदर खुले हुए, बिना मुड़े हुए मतपत्र मिलेंगे? ऐसा किसने किया होगा?' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन या चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना



ऐसा होना मुमकिन नहीं है। निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, 'निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन हमने जो देखा है, उससे लगता है कि उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है।' सपा प्रमुख ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस दौरान पात्र मतदाताओं, खासकर सपा समर्थकों को निशाना बनाया गया। २०२२ के विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि २०१६ में मतदान करने वाले कई लोगों के नाम २०२२ की सूची से गायब थे। भाजपा पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने सवाल किया कि सत्ताधारी दल किसे 'घुसपैठिया' मानता है? उन्होंने कहा, 'छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आते ही घुसपैठियों का मुद्दा फिर से उठाया जा रहा है। भाजपा को साफ करना चाहिए कि घुसपैठिये कौन हैं?' चीन का जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि अगर चीन भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है, तो क्या उन्हें घुसपैठिया नहीं कहा जाएगा? अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा मतदाता सूची संशोधन का इस्तेमाल चुनिंदा लोगों के नाम हटाने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा, ष्हम भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे, लेकिन हमें उन 'प्रीपेड' पार्टियों और नेताओं से भी सावधान रहना होगा, जिन्हें 'ओटीपी' (निर्देश) कहीं और से मिलते हैं।' अंत में, उन्होंने मांग रखी कि फर्जीवाड़े और असली मतदाताओं के नाम हटने से रोकने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ा जाए और मतदान प्रक्रिया में बायोमेट्रिक सत्यापन लागू किया जाए।

सआदतगंज तिहरे हत्याकांडः पीड़ित परिवार से मिले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और नीरज सिंह, दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा

लखनऊ। सआदतगंज में सोमवार को हुए तिहरे हत्याकांड के बाद मंगलवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के प्रदेश



उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। घटनास्थल पर पहुंचे उप– मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। डिप्टी सीएम ने मौके पर मौजूद पुलिस के उच्च अधिकारियों को मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बीजेपी उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने भी पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया और कानून–व्यवस्था के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। क्षेत्र में तनाव और जन–आक्रोश को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।अब हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सआदतगंज पुलिस और जांच एजेंसियां इस हत्याकांड में आगे क्या कदम उठाती हैं। क्या आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो पाएगी? घटना के पीछे के मुख्य कारणों और साजिश का खुलासा कब तक होता है? प्रशासनिक स्तर पर जांच तेज कर दी गई है और पुलिस की कई टीमें संदिग्धों की ध रपकड़ के लिए दबिश दे रही हैं।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

कैलाश खेर की आवाज पर झूमे श्रद्धालु, 'एक शाम राम के नाम' में भक्ति और संगीत का संगम

कानपुर। परेड ग्राउंड में रविवार को 'एक शाम राम के नाम' कार्यक्रम में भक्ति, संगीत और अध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिला। सूफी और लोक संगीत गायक कैलाश





खेर ने भगवान श्रीराम के भजनों से लेकर अपने लोकप्रिय गीतों तक की प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और जय श्रीराम के जयघोष के साथ हुई। मैथिली और मनु बहनों ने 'राम सिया राम, सिया राम जय जय राम' भजन प्रस्तुत कर भक्तिमय माहौल बना दिया। इसके बाद 'ठुमक ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनियां' भजन के जरिए भगवान राम के बाल स्वरूप और उनकी बाल लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया गया। 'श्री रामचंद्र पालु भज मन' की प्रस्तुति ने भी श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। वहीं, मिथिला की परंपरा पर आधारित 'मिथिला का कण–कण खिला, जमाई राजा' गीत पर दर्शकों ने दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाई। राम–सीता के स्वयंवर प्रसंग पर आधारित 'पहनो जयमाला' गीत ने भी लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद कैलाश खेर की प्रस्तुति के लिए मंच तैयार हुआ। मंच की सामान्य लाइटें बंद कर लेजर लाइटें चालू की गईं तो पूरा परिसर रोमांचक माहौल में डूब गया। कैलाश खेर के मंच पर पहुंचते ही दर्शकों ने जोरदार तालियों और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। रंग–बिरंगी रोशनी से सजा मंच आकर्षण का केंद्र बन गया। इससे पहले श्रीरामलीला सोसायटी परेड की ओर से तैयार वीडियो भी स्क्रीन पर दिखाया गया। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना था। कैलाश खेर ने 'अरे मैं राम नाम ही भजूं रे, राम ही पार लगावे', 'पिया के रंग रंग दीनी ओढ़नी' और 'तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना' जैसे गीतों से समां बांध दिया। उन्होंने कानपुर को 'कान्हापुर' बताते हुए कहा कि यह पावन धरती है। उन्होंने कहा कि भारत गायकों का देश है, जहां लोग पुलिस की ड्यूटी करते हुए, साइकिल चलाते हुए, गाड़ी में और सड़क पर भी गुनगुनाते नजर आते हैं। इसके बाद 'कैसे बताएं कि तुमको चाहें' गीत पर दर्शक झूम उठे। 'कौन है, कौन है वो, कहां से वो आया' और 'प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी' जैसे गीतों ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। कैलाश खेर ने कहा कि वह भारतीय संस्कृति और अध्यात्म को ध्यान में रखकर ही गीत लिखते और गाते



हैं। उनके गीतों ने पूरे आयोजन को भक्ति और संगीत के रंग में रंग दिया। होटल लैंडमार्क में पद्मश्री कैलाश खेर का सोसाइटी के पदाधिकारियों ने पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। अध्यक्ष महेंद्र मोहन गुप्त, मंत्री आलोक अग्रवाल समेत हर्ष, प्रवीण, कनिष्का और शिल्पी अग्रवाल ने तिलक लगाकर, आरती उतारकर और रामनामी व रुद्राक्ष माला भेंटकर अभिनंदन किया। पुष्पगुच्छ भी भेंट किया।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566
सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178
Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।